



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2597 /2026

आशुतोष कुमार @ आशु

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

ओम प्रकाश सिंह

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. अधिवक्ता श्री अनुज बाजपेयी, जो आवेदक के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सिंह का पक्ष रख रहे थे, सूचना देने वाले के अधिवक्ता श्री ज्योति भूषण और राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना और रिकॉर्ड को पढ़ा।
3. आवेदक मामला अपराध संख्या 278/2025, धारा 103(1) बीएनएस और 4/25 शस्त्र अधिनियम, पुलिस स्टेशन जहानागंज, जिला आजमगढ़ में मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी तरह के सह-आरोपी श्रवण कुमार को इस कोर्ट ने 3.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 42551/2025 में दिए गए आदेश के ज़रिए पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। आवेदक 8.9.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जैसी ही है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

5. सूचना देने वाले के अधिवक्ता और राज्य विधि अधिकारी ने जमानत की अर्जी का जोरदार विरोध किया है। हालाँकि, सह-आरोपी के बराबर होने और आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने की ऊपर बताई गई बातों पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, और पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि.एल.जे. 93 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो अन्य और 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825 में रिपोर्ट किए गए दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

7. आवेदक- अभिषेक, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोग पक्ष को इस न्यायालय में जमानत रद्द करने का आवेदन देने की आजादी होगी।

9. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और रहने का सबूत संबंधित न्यायालय से सत्यापित किया जाएगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(विकास वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।